

WTO पैनल की सफारिश को लागू करने के लिये बाध्य नहीं भारत

प्रीलिमिंस के लिये:

वशिव व्यापार संगठन, नरियात संबंधी योजनाएँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि

मेन्स के लिये:

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद संबंधी मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद को सूचित किया गया है कि भारत अपनी नरियात प्रोत्साहन योजनाओं पर WTO के विवाद नपिटान पैनल की सफारिशों को लागू करने के लिये बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत ने पैनल के इस आदेश को उच्च स्तर पर चुनौती दी है।

प्रमुख बट्टि

- बीते वर्ष 31 अक्टूबर, 2019 को [वशिव व्यापार संगठन](#) (World Trade Organisation-WTO) के विवाद नपिटान पैनल ने नरिणय दयाि था कि भारत की नरियात संबंधी योजनाएँ (Export-Related Schemes) “**सब्सडि एवं प्रतकिारी उपाय समझौते**” के तहत नषिद्ध सब्सडि (Prohibited Subsidies) की प्रकृति में आती हैं और वशिव व्यापार संगठन के मानदंडों के साथ असंगत हैं।
- WTO के विवाद नपिटान पैनल ने भारत को वशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना को वापस लेने के लिये 180 दिनों की समय-सीमा प्रदान की है।

क्या है विवाद?

- दरअसल 14 मार्च, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative-USTR) कार्यालय ने वशिव व्यापार संगठन (WTO) में भारत की नरियात संवर्द्धन योजनाओं को चुनौती दी थी।
- USTR का तर्क था कि इन योजनाओं के कारण असमान अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। USTR के अनुसार, भारत सब्सडि एवं प्रतकिारी उपाय समझौते (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures- SCM Agreement) के तहत की गई अपनी प्रतबिद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है।
- USTR ने इस संदर्भ में भारत की 5 नरियात प्रोत्साहन योजनाओं (नरियात उन्मुख इकाइयों की योजनाएँ व क्षेत्र-वशिष्ट योजनाएँ) का उल्लेख किया है, जो कि निम्नलिखित हैं-
 - इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (Electronics Hardware Technology Parks Scheme)
 - भारत से मर्चेंडाइज़ नरियात के लिये योजना (Merchandise Exports from India Scheme)
 - नरियात संवर्द्धन कैपिटल गुड्स संबंधी योजना (Export Promotion Capital Goods Scheme)
 - वशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones)
 - शुल्क मुक्त आयात अधिकार-पत्र योजना (Duty free Import Authorization Scheme)
- USTR का मुख्य तर्क यह है कि भारत की उपरोक्त पाँच नरियात संवर्द्धन योजनाएँ, SCM समझौते के प्रावधान 3.1 (A) और 3.2 का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि ये दोनों प्रावधान नरियात सब्सडि देने पर रोक लगाते हैं।

व्यापार विवाद और भारत

- संसद में दी गई सूचना के अनुसार, भारत वर्तमान में WTO में कुल 15 व्यापार विवादों में शामिल है, जिनमें से अधिकांश अमेरिका के साथ हैं। इन विवादों में से 4 में भारत शिकायतकर्त्ता है जबकि 11 विवादों में भारत प्रतविादी है।

वशिव व्यापार संगठन (WTO)

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में मराकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जनिवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
- 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था।
- सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके नरिण्यों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR)

- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) एक अमेरिकी संस्था है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को व्यापार की नीति विकसित करने और अनुशांसा करने तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ता के आयोजन तथा सरकार के भीतर व्यापार नीति के समन्वयन के लिये ज़िम्मेदार है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-not-obliged-to-implement-wto-panel-recommendation>

